हुए क्या यह राशि पर्याप्त है; यदि हां, तो इस संबंध में लक्ष्य किस तरह प्राप्त किया जायेगा; और

(ख) क्या यह सच है कि अन्य विकासशील देशों की अपेक्षा शिक्षा पर भारत में प्रति व्यक्ति कम खर्च किया जा रहा है; यदि हां, तो क्या इस खर्च को इन देशों के बराबर में लाने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों के लिए वर्ष 1990-91 में किया गया बजट प्रावधान कुल राजस्व बजट का 11.1% है।

(ख) यूनेस्को की आंकड़ा वर्ष पुस्तक (1989) के अनुसार वर्ष 1989 में विकासशील देशों में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च 29 डालर था। इसकी तुलना में, वर्ष 1986-87 में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च 112.77 रुपये था।

संसाधनों की अत्याधिकता तथा विकास के अन्य सेक्टरों की मांगों को पूरा करने पर शिक्षा के लिए आवंटनों में वृद्धि करने के प्रयास किये जाते हैं।

Sick Public Sector Undertakings

2381. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Bureau of Public Enterprises (BPE) has taken a decision recently to the effect that sick Public Sector Undertakings would be looked after by the concerned Administrative Ministry;

(b) if so, the details of the sick public sector undertakings; and

(c) whether the Bureau of Public Enterprises propose to suggest measures to improve efficiency to make them profitable, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BHAGEY GOBARDHAN): (a) and (b) All the Central PSEs including the chronic loss-making enterprises are being looked after only by their administrative Ministry/Department.

(c) Improving efficiency and profitability in the Central Public Sector Enterprises is a continuous process. In this regard various steps such as change in product-mix, technology upgradation, improved management practices, energy conservation, modernisation and rehabilitation, organisational restructuring etc. are taken. A new concept of Memorandum of Understanding (MOU) has been introduced which clarifies the mutual obligations of the Public Sector Enterprises and the administrative Ministries in achieving improved performance.

Winding up of sick units of Public Sector Undertakings

2382. SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

SHRI JAGJIT SINGH AURORA:

SHRI RAM JETHMALANI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 97 given in the Rajya Sabha on the 7th August, 1990 and state:

(a) whether Government have reviewed the working of loss incurring public sector units;

(b) if so, what are Government's future plans regarding such units;

(c) whether Government are considering the winding up of some of the sick units of public sector undertakings;

(d) if so, what are the criteria to determine the winding up of sick units; and

(e) whether it is under consideration of Government to permit Board for Industrial Finance and Restructure to look into the affairs of sick units?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMEN-

TATION (SHRI BHAGEY GOBARDHAN): (a) to (e) Review of the working of Central Public Sector Enterprises inclusive of loss making enterprises is a continuous process and appropriate steps are taken to effect improvements in their working on a case to case basis. Some of the steps taken in this direction are financial restructuring, upgradation of technology, administrative re-organisation etc. A new concept of Memorandum of Understanding (MOU) has been introduced which clarifies in mutual obligations of the public sector enterprises and the administrative Ministries in achieving improved performance. The existing provisions in the sick Industrial Companies Act 1985 do not cover Central Public Sector Enterprises and hence these enterprises are outside the purview of Board for Industrial and Financial Re-construction.

Birthday of prophet Mohammed as a National Holiday

2383. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have declared that the birthday of Prophet Mohammed would be observed as a National Holiday from this year onwards;

(b) whether all establishments, in both private and public sectors shall remain closed on this National Holiday; and

(c) if so, the details thereof and if not, the steps to be taken in this regard?

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) to (c) Government have decided to include the birthday of Prophet Mohammed as a holiday in the list of annual holidays for Central Government administrative offices.

जर्मन पनडुब्बी सौदे के संबंध में अधिकारियों की टीम के विदेशी दौरे

2384. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन पनडुब्बियों की खरीद में कथित दलाली दिए जाने के संबंध में अधिकारियों की कोई टीम गत जून में विदेश दौरे पर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस टीम में कौन-कौन अधिकारी शामिल थे और उसके द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या सरकार उसके आधार पर दोषी पाए जाने वाले कतिपय अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजा रमन्ना) : (क) और (ख) एक सरकारी दल ने जून, 1990 में स्विट्जरलैंड और जर्मन संघीय गणराज्य की यात्रा की । इस दल में प्रधान मंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव, श्री भूरे लाल, और केन्द्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त निदेशक श्री एम० डी० शर्मा थे । केन्द्रीय जांच ब्यूरो में पुलिस उप-अधीक्षक श्री डी०एन० चौधरी जर्मन संघीय गणराज्य बोन में इस दल में शामिल हो गए थे । इस दल ने स्विट्जरलैंड सरकार के "फैडरल डिपार्टमेंट आफ जस्टिस एड पोलिस तथा जर्मन संघीय गणराज्य के फैडरल मिनिस्ट्री आफ जस्टिस" को अनुरोध (रोगेटरी) पत्र दिए। जिनमें इन दोनों सरकारों से भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के सौदों के संबंध में मैसर्स एच० डी० डब्ल्यु द्वारा कमीशन की कथित अदायगी के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच में सहयोग देने का अनुरोध किया गया था ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 5 मार्च, 1990 को नियमित मामला सख्या आर.सी. 1(ए)/90/ए.सी.यू.-1